कृषि रोड मैप के अन्तर्गत राज्य में डेयरी विकास की योजना

राज्य की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विकास में गव्य विकास कार्यक्रम की अहम भूमिका है । इसके लिए राज्य में शीर्षस्थ सहकारी संस्थान कम्फेड तथा राज्य सरकार के अधीन गव्य विकास निदेशालय की योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है ।

गव्य विकास की वर्त्तमान स्थिति

राज्य में अब तक कुल ६५८५ दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति गठित है, जो ७७५० गॉवों में आच्छादित है । इन समितियों में लगभग ३.२४ लाख ग्रामीण परिवार जुड़े हुए हैं, जिसमें १४.७ प्रशिक्षित महिलायें सामिल है । राज्य में छः दुग्ध संघ कार्यरत है एवं वर्ष में औसतन कुल ६.०० लाख लीटर प्रतिदिन दूध का संग्रहण एवं विपणन होता है । इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दुग्ध उत्पादकों को उचित दर पर दूध की बिक्री की व्यवस्था तथा उन्नत ढंग से दुधारु जानवरों के रख–रखाव के लिए आवश्यक सुविधायें मुहैया कराई जाती है । साथ हीं शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को उचित दर पर शुद्ध एवं ताजा दूध एवं दुग्ध जन्य पदार्थ सुलभता से उपलब्ध होती है ।

बिहार के ग्रामीण किसानों के आर्थिक विकास तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखाते हुए आमदनी सृजन के विभिन्न आयामों के विकास पर चालू पंच वर्षीय योजना में शेष चार वर्षों के लिए कुल ४७१.७७ करोड़ रुपये की योजनाएँ तैयार की गई है, जिसमें वर्ष ०८–०९ के लिए ११५.९७ करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य–कलाप क्रियान्वित कर राज्य को निम्न प्रकार से विकसित किया जा सकेगा ।

क्रमांक	कार्यकलाप	वर्त्तमान	२०१२ लक्ष्य)
१	दुग्ध उत्पादन	१३८.०० लाख किलो / दिन	१७२.०० लाख किलो / दिन
२	प्रसंस्करण क्षमता सहकारिता)	६.३५ लाख लीटर / दिन	१६.३५ लाख लीटर / दिन
३	दुग्ध संग्रहण सहकारिता)	६.०० लाख किलो / दिन	१२.०० लाख किलो / दिन
४	दुग्ध विपणन सहकारिता)	६.०० लाख लीटर / दिन	९.०० लाख लीटर / दिन
५	प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता / दिन	१५४ ग्राम	१६१ ग्राम
६	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	२७०१	शतप्रतिशत दरवाजे पर
७	टीकाकरण	६६.९५ लाख	शतप्रतिशत
८	चारा / पशु आहार उत्पादन	२६० एम०टी० / दिन	४६० एम०टी० / दिन
९	चारा ब्लॉक निर्माण इकाई	शून्य	१४ १००
१०	फार्म प्रबंधन, समिति	३००० २००७–०८)	८०८६६ २०१२ तक)

	प्रबंधन एवं कृत्रिम गर्भाधान में किसानों का प्रशिक्षण		

डेयरी विकास की योजनाएँ

वर्ष २००८–०९ में राज्य में मुख्य रुप से निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं:–

१. दुग्ध समितियों के गठन की योजना

इस योजना के अन्तर्गत कुल ११३३ समितियों का गठन कर दुग्ध संग्रहण, शीतलीकरण, पशु स्वास्थ्य एवं नस्ल सुधार की सुविधायें प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि लाकर उनके आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है । समिति के गठन के पश्चात् प्रत्येक समिति को रुपया २०,०००.०० के अनुमानित लागत व्यय पर मिल्क कैन, रजिस्टर, दूध जाँच उपकरण एवं उपस्कर उपलब्ध कराये जाते हैं । वर्ष में कुल अनुमानित व्यय रुपया २२६.०० लाख है ।

अधिक मात्रा में दूध संग्रहित करने वाले समितियों में दूध की त्वरित जाँच हेतु रुपया २८,००.०० की लागत पर इलेक्ट्रोनिक मिल्को टेस्टर भी उपलब्ध कराये जाते हैं । वर्ष में कुल ९०५ समितियों को इलेक्ट्रोनिक मिल्को टेस्टर उपलब्ध कराने के लिए रुपया २५३.४० लाख का व्यय अनुमानित है ।

२. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना

ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम प्रजनन केन्द्र स्थापित कर नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत उन्नत नस्ल के पशु उत्पादित किए जाते हैं ताकि भविष्य में अधिक मात्रा तथा लम्बी अवधि तक दूध देने वाले पशु प्राप्त हों । इस कार्यक्रम से दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि लाकर गव्य व्यवसाय को अधिक लाभाकारी बनाया जाता है । एक केन्द्र की स्थापना पर लगभग रुपया ४२,०००.०० का अनुमानित व्यय होता है । कुल २५१ केन्द्रों के लिए अनुमानित लागत व्यय रुपया १०५.४२ लाख है । इसके साथ हीं रुपया ६.०० लाख के लागत व्यय पर एक सूचना पद्धति की भी स्थापना की योजना प्रस्तावित है ।

३. आदर्श डेयरी ग्राम की स्थापना

ग्रामीण स्तर पर चिन्हित मुख्य पथ पर एक ही ग्राम में विभिन्न सुविधायें जैसे दूध ठंढा करने के लिए बल्क कूलर की स्थापना, समिति–सह–सामूदायिक भवन का निर्माण, कृत्रिम गर्भाधान–सह–प्राथमिक उपचार की सुविधा इत्यादि आदान मुहैया कराया जायेगा । प्रत्येक आदर्श डेयरी ग्राम की स्थापना के लिए कुल रुपया १६.५० लाख खर्च अनुमानित है एवं ६० ग्रामों की स्थापना में कुल व्यय रु० ९९०.०० लाख होगा ।

४. मीनी डेयरी की योजना

ग्रामीण स्तर पर प्रगतिशील कृषक बेरोजगार युवक को पाँच शंकर नस्ल गाय की एक इकाई उपलब्ध कराए जाने की योजना है । एक इकाई की स्थापन पर लागत व्यय लगभग रु० एक लाख ग्यारह हजार आँका गया है जिसमें २१ हजार विभागीय अनुदान के रुप में उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष राशि बैंक द्वारा ऋण के रुप में प्रदत्त किया जायेगा । राज्य में कुल ६२२ मीनी डेयरियों की स्थापना के लिए कुल रु० १२४.४० लाख का अनुदान अनुमानित है ।

५ चलंत पशु चिकित्सा क्लिनिक–सह–रोग निरीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना

पशुओं को रोग से बचाने के लिए चलंत प्रयोगशाला की स्थापना प्रस्तावित है । क्लिनिक में आवश्यक उपकरण एवं दवा के साथ पशु चिकित्सक लैस रहेंगे एवं समितियों/ग्रामों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चिकित्सा के लिए जायेंगे । वर्षा में ७ क्लिनिक–सह–प्रयोगशाला की स्थापना पर रु० ३५.०० लाखा का व्यय अनुमानित है ।

६ पशु प्रजनन इकाई की स्थापना

ग्रामीण स्तर पर पशु प्रजनन इकाई की स्थापना की जायेगी जहाँ वंशावली एवं संतती परीक्षण पर आधारित उच्च कोटी के बीर्य कार्य अभिलेखा रखाते हुए कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से अधिक संख्या में बछरियों का उत्पादन किया जायेगा । प्रति प्रजनन इकाई की स्थापना के लिए रु० ४.०० लाखा की दर से कुल ५० इकाई स्थापित की जायेगी जिसपर रु० २००.०० लाखा का निवेश अनुमानित है एवं ८०,०००.०० रु० प्रति इकाई की दर से ४०.०० लाखा रु० अनुदान के रुप में व्यय अनुमानित है । लाभान्वित द्वारा योजना लागत का १० प्रतिशत व्यय वहन किया जायेगा तथा शेष राशि बैंक ऋण के रुप में उपलब्ध कराई जायेगी ।

७ पशु स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम की योजना

इस योजना अन्तर्गत रु० ५००.०० लाखा के लागत व्यय पर पटना स्थित पशु आहार कारखाना के वर्त्तमान क्षमता को विस्तारित करना है । इसके अतिरिक्त रु० १५.०० लाखा के लागत पर मिनरल मिक्स्चर प्लांट की स्थापना भी प्रस्तावित है । सूखाग्रस्त, बाढ़ग्रस्त एवं आपदा प्रभावित वाले क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति के लिए पशुओं को सूखा चारा उपलब्ध कराने हेतु बेगुसराय, मुजफ्फरपुर एवं भोजपुर में रु० ७५.०० लाखा के लागत पर फोडर ब्लॉक मेकिंग इकाई की स्थापना प्रस्तावित है । साथ हीं पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशीप में ३० इकाईयों की स्थापना की जानी है जिसपर प्रति इकाई रु० १.३० लाखा अनुदान के रुप में उपलब्य होगा तथा शेष राशि बैंक द्वारा ऋण के रुप में उपलब्ध कराई जायेगी ।

८ हरा चारा प्रत्यक्षण की योजना

ग्रामीण स्तर पर दूध उत्पादन में वृद्धि लाने, दूध उत्पादन में लागत व्यय कम करने के लिए विभिन्न मौसम में हरा चारा प्रत्यक्षण की योजना को कार्यान्वित किया जाना है । समिति स्तर पर लाभान्वितों को उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लॉट में हरा चारा का प्रत्यक्षण कराया जायेगा । प्रति प्लॉट अनुमानित लागत व्यय रु० १,६००.०० आँका गया है । कुल १२७९ प्लॉट में प्रत्यक्षण के लिए रु० २०.४६ लाखा का व्यय अनुमानित है ।

९ गव्य विज्ञान में प्रशिक्षणा की योजना

राज्य के किसानों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षित करने के लिए राज्य के बाहर स्थित संस्थानों तथा राज्य के अन्तर्गत कम्फेड एवं डी०एन०एस० पटना स्थित संस्थानों में दुधारु जानवरों के उचित रखारखाव, पशु स्वास्थ्य, कृत्रिम गर्भाधान, समिति के सचिवों तथा सदस्यों को प्रशिक्षित किए जातें हैं तथा समिति में जाकर जागरुकता कार्यक्रम के तहत् प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे गव्य व्यवसाय को आधुनिक एवं विकसित तरीके अपनाकर अधिक से अधिक दूध उत्पादित कर अपनी आमदनी को बढ़ा सके । वर्षा में कुल १५,१३६ किसानों को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत् प्रशिक्षित किए जायेंगे जिसपर कुल रु० १९६.८० लाखा का व्यय अनुमानित है ।

१० नए डेयरी प्लान्ट की स्थापना

भविष्य में राज्य में दुग्ध उत्पादन की असीम वृद्धि की संभावना को देखते हुए नालन्दा में रु० १२०.६३ करोड के लागत पर डेयरी/पाउडर/टेट्रापैक प्लान्ट स्थापित किए जा रहे हैं । २०.०० करोड़ रु० के लागत परं रोहतास जिला के डेहरी ओन सोन में नये डेयरी प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना तथा समस्तीपुर एवं बेगुसराय में वर्त्तमान डेयरी प्लांट के सुदृढ़िकरण एवं उन्नयन भी प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त रु० ४५०.०० लाखा के लागत पर मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर के वर्त्तमान डेयरी प्लांट के सुदृढ़िकरण, उन्नयन एवं आधुनिकीकरण की योजना भी प्रस्तावित है ।

११ बल्क मिल्क कूलर/स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र की स्थापना

ग्रामीण क्षेत्रों में संग्रहित किए जा रहे दूध के गुणवत्ता को अच्छुन्न रखाने के लिए ४७ समितियों में १०८१.०० लाखा रु० के अनुमानित लागत पर बल्क कूलर की स्थापना प्रस्तावित है । साथ हीं दुग्ध समितियों के कार्यकलापों में पारदर्शिता एवं आधुनिकीकरण लाने के लिए ११६ समितियों में कुल रु० २३८.०० लाखा के अनुमानित लागत पर स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित है ।

१२ दूध विपणन की व्यवस्था

ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित दूध को संग्रहित एवं विधायन कर शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर शुद्ध एवं ताजा दूध तथा दुग्ध जन्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए रु० २०.०० लाखा के लागत पर रेफ्रीजरेटेड वैन, रु० १८७.५० लाखा के लागत पर ७५ इन्सुलेटेड बॉक्स एवं डीपफ्रीज से सुसज्जितत हॉल डे बूथ, रु० ६६.०० लाखा के लागत पर ११ वाक–इन कोल्ड स्टोरेज तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों पर रु० २७.२० लाखा के लागत पर १३६ कोल्ड चैन के अन्तर्गत भिजीकूलर्स /डिपफ्रीज की स्थापना प्रस्तावित है ।

१३ ई०आर०पी०सिस्टम की स्थापना

डेयरी के समस्त कार्यकलापों का प्रबंधन एवं अभिलेखान एक केन्द्रीयकृत कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से करना प्रस्तावित है जिसकी स्थापना पटना स्थित कम्फेड मुख्यालय एवं पटना स्थित डेयरी प्लांट में करना प्रस्तावित है । अनुमानित लागत व्यय रु६ २००.०० लाखा है ।

१४ पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन

राज्य में चलाये जा रहे गव्य विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा एवं आकलन कराया जायेगा जिसपर परियोजना लागत का २ प्रतिशत व्यय अनुमानित है ।